



# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 214

No. 224]

DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

[N.C.T.D. No. 214]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

(पंजीकरण एवं स्टाम्प शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2016

सं.फा.1(953) / पंजी. शाखा / मंड.आयु. / मुख्या. / 2014 / 2617.—जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 27 की उपधारा (3) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना सं. एसओ/1726 (संख्या फाइल 215/61न्याय/2) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखित अवमूल्यांकन रोकथाम) नियमावली, 2007 के नियम 4, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बांधों के बीच तथा नदी तल में अवस्थित भूमि व कृषि भूमि की बिक्री/अन्तरण से संबंधित प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के प्रयोजन के लिए च्यूनतम दरों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 04.अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं. फा. सं.फा.1(953)/पंजी.शाखा / मंड.आयु. / मुख्या. / 2014 / 191के अनुसार अधिसूचित किया गया था।

अब, रिट याचिका (सिविल)सं.7934 / 2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 04.अगस्त, 2016 के निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा उक्त अधिसूचना को रद्द करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उप-राज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर,  
ए.अनबरासु, सचिव (राजस्व)

**REVENUE DEPARTMENT  
(REGISTRATION AND STAMP BRANCH)**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th October, 2016

**No.F.1(953)/Regn.Br./Div.Com/HQ/2014/2617.**—Whereas in exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 27 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and Rule 4 of the Delhi Stamp (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules, 2007 read with the Ministry of Home Affairs, Government of India Notification No. S.O. 1726 (No.F.215/61/Judl II) dated the 22nd July, 1961, the minimum rates for the purpose of chargeability of stamp duty on the instruments related to sale/transfer of agricultural land and land situated in river bed between forward bunds, were notified vide Notification No. F.1(953)/Regn. Br./Div.Com/HQ/2014/191 dated the 4th August, 2015 under the provisions of the said Act.

Now, in pursuance of the Judgement dated 04th August, 2016 of Hon'ble High Court of Delhi in Writ Petition, (Civil) No. 7934/2015, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby revokes the said notification.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
A. ANBARASU, Secy. (Revenue)